सेमी कंडक्टर निर्माण नीति 2023 का मसौदा तैयार, जितना पैसा केंद्र से मिलेगा उसका आधा यूपी सरकार भी देगी

यूपी में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लगाने पर दोहरा लाभ

नीति

■ अजित खरे

लखनऊ। सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे नए क्षेत्र में निवेश को लाने के लिए योगी सरकार कंपनियों को बड़ी रियायत देगी। राज्य में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनियों को केंद्र सरकार जितनी वित्तीय मदद मिलेगी, तो यूपी सरकार उसका 50 प्रतिशत अपनी ओर से देगी। इस तरह निवेशको को दोहरा फायदा होगा। यह नहीं निवेशकों को जमीन के रेट का 25 प्रतिशत हिस्सा अपनी ओर से देगी। इस छूट रियायत की सीमा इससे अधिक भी हो सकती है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नई सेमी कंडक्टर नीति 2023 का मसौदा तैयार कर लिया है। अब इसे जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। एफडीए नीति के बाद यह दूसरी नीति है जिसके जरिए सरकार यूपी में भारी निवेश का राह आसान बनाने जा रही है। इसीलिए दूसरे राज्यों से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सरकार निवेशकों अधिक से अधिक रियायतें देकर बुलाना चाहती है। केंद्र की वित्तीय मदद मिलने के बाद उसका आधा हिस्सा अलग से निवेशकों को देने का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है।

सीएम योगी से गुरुवार को लखनऊ में बेल्जियम के भारत में राजदूत डिडिएर वेंडरहासेल्ट के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की।

25 फीसदी जमीन के मूल्य का यूपी सरकार देगी

भारत अभी सेमीकंडक्टर के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के निर्माण में मूल आधार चिप ही होता है। अब हाल में अमेरिकन कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है।

अब यूपी सरकार चाहती है कि यूपी दुनिया भर की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों यहां निवेश करें।

सहूलियतों को खुलेगा पिटारा : निवेशक को जमीन खरीद के अलावा स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया है। विद्युत कर में भी पूरी छूट दी जाएगी। सेमीकंडक्टर उद्योग एक विशिष्ट प्रकार का उद्योग है। इसके लिए तकनीकी तौर पर दक्ष स्टाप की जरूरत होती है। इसलिए प्रशिक्षण को अहम मानते हुए प्रति प्रशिक्षु 50000 रुपये सरकार कंपनी को देगी। शोध व अनुंसधान के लिए भी एक करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। पेटेंट के लिए अधिकतम दस करोड़ दिए जाएंगे। यही नहीं इलेक्ट्रानिक्स नीति में बिल्डिग बाइलाज में जो अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशिया (एफएआर) की व्यवस्था की है, उसका लाभ इन निवेशकों को भी मिलेगा।

रक्षा, अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में भागीदारी करेगा बेल्जियम

लखनऊ। यूरोपियन देश किंगडम ऑफ बेल्जियम के भारत में राजदूत डिडिएर वेंडरहासेल्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ आये चार सदस्यीय दल ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न सेक्टरों में साझेदारी के लिए इच्छा व्यक्त की है। खासकर वेस्ट मैनेजमेंट, डिफेंस एंड स्पेस, सोलर प्रोजेक्ट और सेमी कंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में बेल्जियम की ओर से गहरी रुचि दिखाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान किंगडम ऑफ बेल्जियम के राजदूत डिडएर वेंडरहासेल्ट ने उत्तर प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों की तारीफ की।

औद्योगिक गढ़ बनकर उभरेगा लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के मास्टर प्लान - 2041 के तहत लखनऊ प्रदेश का औद्योगिक गढ़ बन कर उभरेगा। साथ ही उन्नाव में औद्योगिक एवं संस्थागत विकास को भी यह मास्टर प्लान बढ़ावा देगा। इन सबका फायदा कानपुर -उन्नाव को भी होगा। लखनऊ में लीडा का दायरा बिजनौर, नटकुर, कुरौनी जैतिखेड़ा से शुरू होकर लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ उन्नाव के आजाद चौराहा तक 299 वर्ग किमी तक था। अब यूपीसीडा यहां आवासीय व व्यावसायिक सुविधायुक्त टाउनशिप, आईटीबीपी, आपदा प्रबंधन और फॉरेंसिक साइंस इंस्टिट्यूट के कैंपस, वेयरहाउसिंग के प्रोजेक्ट ला रहा है। सरोजनीनगर में बीजी लिंक इंफ्रा, जिमी गार्डन, संतुष्टि इन्क्लेव समेत कई प्रोजेक्ट इसी दायरे में आएंगे।